November, 1994. The claimant has the choice to file the case either with the MACT available at his normal place of residence or the MACT which has the jurisdiction over the place of accident. The claim is payable on the basis of 'no fault'. The claimant has the option to file a case in the MACT if the compensation as provided is not acceptable to him. Apart from this, the claimants can also get their cases expedited through Lok Adalats and by availing the Jald Rahat Yojana Scheme in case of non-fatal injuries, introduced at selected centres by the GIC in the year 1991. These measures will help in the speedy disposal of insurance claims of road accident victims.

बैंकों में अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की गई राशि

70. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान बड़ोदरा, सूरत, भरूच और पंचमहल जिलों के अनिवासी भारतीयों द्वारा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में कुल कितनी राशि जमा की गई;

(ख) उक्त जिलों के अनिवासी भारतीयों द्वारा किन-किन बैंकों में सर्वाधिक राशि जमा की गई; और

(ग) क्या सरकार ने इन अनिवासी भारतीयों को निवेश करने हेतु एवं अधिक विदेशी मुद्रा को और अधिक बैंकों में जमा कराने हेतु प्रोत्साहन देने हेतु क्या-क्या आकर्षक योजनाएं तैयार की हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महालेखाकार के कार्यालय में विभिन्न खातों में जमा की गई राशि

71. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान महालेखाकार कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि राज्यवार जमा हुई ;

(ख) कितनी राशि गुमशुदा लेखाओं के अन्तर्गत जमा की गई और कितनी राशि जमाकर्ताओं के खातों में जमा की गई ;

(ग) उक्त वर्षों में कितने जमाकर्ताओं को उनकी सेवा-निवृत्ति होने एवं सेवारत रहते मृत्यु होने पर अन्तिम रूप से सम्पूर्ण राशि भुगतान कर दी गई और कितनों को भुगतान किया जाना शेष है ; और

(घ) राज्य सरकार के कर्मचारियों की जमा राशि और अन्तिम भुगतान एवं गुमशुदा खातों में जमा राशि तथा गुमशुदा खातों की राशि को सही खातों में वर्षवार जमा की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि संबंधित राज्य सरकारों के लोक लेखा का एक हिस्सा होती है और यह राज्य के विषय की एक मद है। तथापि, सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Interim report of the Fifth Pay Commission

72. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have asked the Fifth Pay Commission to

submit an interim report with a view to granting immediate relief to the Central Government employees;

(b) if so, the details thereof;

(c) by when the Commission is likely to submit its final report;

(d) whether the recommendations of the Pay Commission will be applicable from the date of the constitution of the Pay Commission; and

(e) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) The Government have by a notification issued on 12.1.95 added to the terms of reference of the Fifth Pay Commission the following:—

2(f) "The Commission may consider the demands of the staff side of the National Council of the JCM for grant of another instalment of interim relief and merger of a further portion of DA with pay (for the purpose of gratuity alone) and send a report thereon, if the Commission feels that it will not be possible for them to submit their final Report within a period of 18 months from the date of its appointment.

While considering these demands, the Fifth Central Pay Commission may take into account the interim relief and the merger of 20% of DA with pay only for the purpose of gratuity, already sanctioned by the Government in September, 1993."

(d) and (e) These aspects will be examined by the Government after the report of the Commission becomes available.

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋण-खाते

73. **श्री ईश दत्त यादव :**
श्री आस मोहम्मद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1994 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल ऋण-खातों की संख्या कितनी थी, जिन्हें ऋण दिये गये और उन खातों में इस तरह राज्यवार तथा बैंकवार कुल बकाया राशि कितनी-कितनी थी ;

(ख) प्राथमिकता वाले क्षेत्र में दिए गए ऋण के सिलसिले में ऋण खातों के से संबंधित उसी अवधि के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को दिए गए ऋण के संबंध में उसी अवधि के ऋण खातों संबंधी आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही हैं और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायगी।

Malpractice/corruption in Banks

74. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a newsitem which appeared in the 'Dainik Jagran' of 29th December, 1994 under the caption "Teen Bank Adhikarion Sahit Panch Log Bhrastachar Ke Doshi";

(b) if so, the details in this regard;

(c) whether Government have identified other banks for such malpractices/corruption; and

(d) what penal action has been taken against those officers who have been found guilty?